Will and

संख्याः ^{36†} /XVIII(3)/2018-02(07)2018

प्रेषक.

विनोद प्रसाद रतूड़ी सचिव (प्रभारी) उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग-3

देहरादूनः दिनांक 28 जून, 2018

विषय:- सरकारी मूमि/ उत्तराखण्ड सरकार की भूमि पर Government Grant Act के अन्तर्गत आवंटित पट्टेदारों की भूमि अधिग्रहण पर देय प्रतिकर मुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ने अपने पत्र संख्या— 232II/ऑलवेदररोड/भूमिअधिग्रहण/2017—18, दिनांक 06 मार्च, 2018 से सर्व ऋतुमार्ग परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 धरासू—गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग तथा 94(134) धरासू—यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण हेतु अर्जित की जा रही सरकारी भूमि/उत्तराखण्ड सरकार की भूमि पर Government Grant Act के अन्तर्गत आवंदित पट्टे धारकों को प्रतिकर की धनराशि के भुगतान में आ रही कितनाई/समस्याओं के सम्बन्ध में शासन से दिशा निर्देश का अनुरोध किया गया है। 2— इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चारधाम/सर्व ऋतुमार्ग परियोजना के चौड़ीकरण हेतु भूमि अर्जन की कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए से उजे के प्रावधानानुसार की जा रही है। उक्त अधिनियम की धारा उजी में सक्षम प्राधिकारी को भुगतान योग्य क्षतिपूर्ति का निर्धारण करने की शक्ति प्रदान की गयी है एवं उएच में धनराशि जमा करने एवं भुगतान की व्यवस्था है। उक्त के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 1—1(5)/1981—राजस्व—2—565/81ए दिनांक 05 जून, 1981 के प्रावधान उत्तराखण्ड राज्य में लागू किया जाना उचित नहीं है।

3— इसके अतिरिक्त भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3(r)(iii) Land Owner में निम्न रमान्या है

"Who is entitled to be granted Patta rights on the land under any law of the State including assigned lands."

अतः राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण हेतु अर्जित की जा रही सरकारी भूमि / उत्तराखण्ड सरकार की भूमि पर Government Grant Act के अन्तर्गत आवंटित पट्टे धारकों के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

संख्याः ॐ /XVIII(3)/2018, तद्दिनांक।

आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून। (1)

महाप्रबन्धक (परि०), राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लि०, मकान (2)नं0 58/37 प्रथम तल, बलवीर रोड़, देहरादून।

समस्त अपर जिलाधिकारी / सक्षम प्राधिकारी, भूमि अर्जन, उत्तराखण्ड। (3)

वरिष्ठ निजी सचिव-अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

आज्ञा से.

संयुक्त सचिव।